Kothagudem Thermal Power Station

956. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether techno-economic clearance and coal linkages have been given to 2x250 M. W. Kothagudem Thermal Power Station in Andhra Pradesh;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) The proposal for installation of Kothagudem Thermal power Station Stage V (2X250 MW) of Andhra Pradesh State Electricity Board has been techno-economically cleared by the Central Electricity Authority at an estimated cost of Rs. 1890 crores subject to the following conditions:

(i) Confirmation of coal linkage by Standing Linkage Committee.

(ii) Utilisation of fly ash as per stipulations of the Ministry of Environment & Forests.

The Standing Linkage Committee, Ministry of Coal, have confirmed coal linkage envisaging supply of coal by M/s. Singareni Collieries Company Ltd.

Restructuring the Management of National Hydro-Electric Power Corporation

*957. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal for restructuring the management of the National Hydro Electric Power Corporation (NHPC) Ltd.;

(b) if so, what arc the details in this regard; and

(c) to what extent it would increase the efficiency of NHPC?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) At present there is no proposal under consideration of the Govt. to restructure the management of NHPC.

(b) and (c) Do not arise.

Ailing Power Plants of Bihar and Orissa SEBs

958. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the poor financial health of the Bihar and Orissa State Electricity Boards and the refusal of the international power equipment manufacturing companies and BHEL to modernise their ailing power plants on build, operate and transfer basis;

(b) if so, whether Government propose to come to the rescue of the SEBs of Bihar & Orissa; and

(c) if so, what steps are contemplated by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) For conducting a study aimed at improving the performance of the power sector in Orissa the World Bank has sanctioned an amount of US $ 2 million for restructuring the electricity industry in the State of Orissa using funds under the project Preparation Facility of the Bank. On the basis of a request made by the Government of Bihar, the World Bank has been approached by the Central Government to support a similar study in respect of Bihar.

बिहार में जल विद्युत परियोजनाएं

959. श्री एस० एस० अहलुवालियाः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः

(क) क्या यह सच है कि नेपाल से आने वाली

तथा बिहार से होकर गुजरने वाली नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की अच्छी सम्भावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार से विचार-विमर्श अथवा समझौता किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू): (क) से (घ) दो प्रमुख नदियां अर्थात् गंडक और कोसी नेपाल से बहती हुई भारत में प्रवेश कर गंगा नदी में मिलती हैं। नेपाल में इन दो नदियों अर्थात् गंडक की सहायक नदी पर बुरडी गंडाकी (600 मे० वा०) और कोसी नदी पर सापता कोशी (3300 मे० वा.) पर दो प्रमुख परियोजनाओं के सम्बन्ध में सर्वेक्षण और अन्वेषण से संबंधित मामलों पर इस समय नेपाल से विचार-विमर्श चल रहा है। दिसम्बर, 1993 जल संसाधन मंत्री के नेपाल दौरे के दौरान दोनों देश इन परियोजनाओं की रूपात्मकताओं और परियोजनाओं सम्बन्धी अन्वेषण कार्यों के ब्यौरों को अंतिम रूप दिए जाने की दिशा में कदम उठाने के लिए सहमत हो गए हैं।

वित्तीय अभावों के कारण बिहार में विद्युत उत्पादन में रुकावट

960. **श्री एस० एस० अहलुवालिया:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य की अनेक विद्युत परियोजनाओं में वित्तीय अभावों के कारण विद्युत उत्पादन आरम्भ नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य की विद्युत परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए ऐसे वित्तीय अभावों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू): (क) और (ख) बिहार में विद्युत परियोजनाओं के कार्य में प्रगति तथा इनको पूरा करने में वित्तीय समस्याओं के कारण बाधा आई है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत क्षेत्र हेतु 2120.83 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय में संशोधन करके वर्ष 1992-93 के लिए व्यय की अनुमानित राशि केवल 169.06 करोड़ रुपये कर दी गई है और वर्ष 1993-94 के लिए प्रत्याशित व्यय की राशि भी प्रायः इसी के समान 169.40 करोड़ रुपये है;

(ग) विद्युत क्षेत्र के भौतिक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ बिहार सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है कि राज्य में विद्युत उद्योग की पुनः संरचना किए जाने की दृष्टि से तैदानिक अध्ययन कार्य किए जाने के लिए सहायता हेतु विश्व बैंक से अनुरोध किया जाए।

Increasing the Power Generation

961. SHRI S.K.T. RAMACHANDRAN: Will the Minister of POWER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 570 given in the Rajya Sabha on the 7th December, 1993 and state:

(a) whether it is a fact that the per capita consumption of power in India is very low compared with that of advanced countries, if so, what measures are taken by Government to improve this situation; and

(b) whether the power generated by the new private enterprises will be absorbed in the existing power grids of the country or new private enterprises will have their own electrical grid?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir. Various measures are being taken to improve the availability of power in our country so that the growing demand for power is substantially met. The measures include taking up of new projects for implementation, mobilising additionality of resources from private sector companies for the capacity addition programme in distribution and generation, expediting commissioning of new generating capacity, implementation of short gestation projects, improving the performance of existing power stations through renovation and modernisation and uprating of their performance, reduction in T & D losses, implementation of demand side